एस. पी. गोयल और जी. सी. मितल से पहले, जे.जे. के समक्ष

रामनारायण पालीवाल–आवेदक,

बनाम

आयकर आयुक्त,-प्रतिवादी।

आयकर संदर्भ संख्या 27 आफ 1977

अक्टूबर 18, 1985.

आयकर अधिनियम (1961 का XLII) - धारा 171 - हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें एक कर्ता, उसकी विधवा मां और उसके नाबालिग बेटे शामिल हैं - ऐसे परिवार जो एक फर्म में भागीदार के रूप में व्यवसाय करते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार को इस रूप में मान्यता दी गई है और इसका मूल्यांकन किया गया है। पिछले वर्ष - ऐसे परिवार की संपत्ति का आंशिक विभाजन - क्या वैध है।

माना गया कि एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी अन्य चिंता का भागीदार बन सकता है। एक बार एच.यू.एफ. यदि वह एक निर्धारिती बना हुआ है और उसे इस रूप में मान्यता दी गई है, तो एच.यू.एफ. का आंशिक विभाजन हो सकता है। संपत्तियां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 171 को पढ़ने पर एच.यू.एफ. के आंशिक विभाजन का दावा करने के लिए निर्धारिती के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। संपत्ति, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा कि मां विभाजन का दावा करने की हकदार थी या नहीं, और यहां तक कि अगर कर्ता एकमात्र पुरुष सह-साझेदार था, तो भी वह विभाजन को प्रभावित कर सकता था। आयकर कानून और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 171 में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। एच.यू.एफ. के सदस्य माँ और बेटे हैं, ऐसे H.U.F. एच.यू.एफ. के पूर्ण या आंशिक विभाजन को प्रभावित करने वाले कानून में वर्जित है। संपत्तियां। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एच.यू.एफ. का वैध आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है। एक विधवा माँ और उसके बेटे के बीच संपत्ति।

(पैरा 5)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच) चंडीगढ़ द्वारा बनाया गया आयकर संदर्भ, इस माननीय न्यायालय की राय लेने के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का संदर्भ देता है, जो उत्पन्न होता है ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 29 जुलाई 1976 को आई.टी.ए. 1975-76 का क्रमांक 805 एवं आर.ए. निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 1976-77 की संख्या 141।

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि एक विधवा मां और उसके बेटे के बीच एचयूएफ की संपत्ति का वैध आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है।"

याचिकाकर्ता के वकील बलवंत सिंह गुप्ता।
प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान, अधिवक्ता अजय मित्तल।

निर्णय

गोकल चंद मित्तल, जे.

(1) मामले की सराहना करने के लिए, निम्नलिखित वंशावली तालिका
ध्यान में रखा जा सकता है:

राम चंदर पालीवाल=रामप्यारी
राम नारायण = पत्नी
चार नाबालिग बेटे
एक बेटी

(2) राम चंदर पफीवाल हिंदू अविभाजित परिवार (संक्षेप में 'एच.यू.एफ.') के कर्ता थे, जो धन उधार देने का व्यवसाय करते थे और अचल संपत्ति के मालिक थे। 3 सितंबर, 1963 को उनकी मृत्यु हो गई। एच.यू.एफ. रामनारायण को कर्ता के रूप में जारी रखा।

(3) मेसर्स राम नारायण सत नारायण के नाम और शैली के तहत एक फर्म 8 दिसंबर, 1965 को शुरू की गई थी और राम नारायण एच.यू.एफ. का प्रतिनिधित्व करते थे। 35 प्रतिशत की अपनी हिस्सेदारी के साथ उक्त फर्म में भागीदार बन गया। एच.यू.एफ से बाहर उन्होंने जो धनराशि निवेश की वह रु. उस फर्म में भागीदार के रूप में 45,000 रु. 31 मार्च, 1973 को एच.यू.एफ की राजधानी; मेसर्स राम नारायण सत नारायण की पुस्तकों में रुपये के रूप में दिखाया गया था। 1,18,321.42. उक्त रकम रामनारायण और श्रीमती ने आपस में बांट ली थी। राम प्यारी और रु. उनमें से प्रत्येक को 59,160.71 रुपये आवंटित किए गए थे। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के अलग-अलग खाते मेसर्स राम नारायण सत नारायण की पुस्तकों में रुपये के प्रारंभिक क्रेडिट शेष के साथ खोले गए थे। 59,160.71. 2 अप्रैल, 1973 को आंशिक विभाजन का एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें उपरोक्त विभाजन की शर्तें दर्ज थीं। 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 171 के तहत आंशिक विभाजन का दावा एच.यू.एफ. द्वारा किया गया था। आयकर अधिकारी ने आंशिक विभाजन

के लिए निर्धारिती के दावे को स्वीकार नहीं किया, सबसे पहले क्योंकि श्रीमती। आंशिक बँटवारे के ज्ञापन में राम प्यारी को गलत तरीके से सह-भागीदार बताया गया था और दूसरे, क्योंकि विधवा माँ बँटवारे के लिए बाध्य नहीं कर सकती थी। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि कम से कम दो 'सह-पार्सनर का अस्तित्व आवश्यक था। विभाजन का दावा. एच.यू.एफ. अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय सहायक आयुक्त, (अपीलीय प्राधिकारी) ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, विद्या बेन बनाम जेएन भट्ट[1] और जय प्रकाश बनाम राम काली[2] के प्रावधानों पर भरोसा किया। यह निष्कर्ष कि एक महिला उत्तराधिकारी संयुक्त हिंदू संपत्ति के विभाजन का दावा कर सकती है। नतीजतन, अपील स्वीकार कर ली गई और अधिनियम की धारा 171 के तहत आंशिक विभाजन की अनुमति दी गई। विभाग आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में आया। ट्रिब्यूनल ने 29 जुलाई, 1976 के आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी और अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद, श्रीमती के निष्कर्ष देने के बाद आयकर अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया। आंशिक बँटवारे के ज्ञापन में राम प्यारी को गलत तरीके से सह-वारिसदार बताया गया था क्योंकि कानून के अनुसार उसे सह-वारिसदार नहीं होना चाहिए और वह बँटवारे का दावा करने की हकदार नहीं थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबसे पहले उसने मुल्ला के हिंदू कानून के पैरा 316 पर भरोसा किया कि जब तक बेटे एकजुट हैं तब तक मां बंटवारे का दावा नहीं कर सकती और चूंकि राम प्यारी का एक ही बेटा था और चूंकि वह बेटा बंटवारे का दावा नहीं कर सकता, यानी अपने खिलाफ बंटवारा कर सकता है। कोई बंटवारा नहीं हो सका. निर्धारिती की ओर से इस प्रस्ताव के लिए हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 की धारा 3(3) के प्रावधानों पर भरोसा रखा गया था कि एक हिंदू विधवा को पुरुष मालिक के रूप में विभाजन का दावा करने का समान अधिकार होगा और इसलिए, अपीलीय सहायक आयुक्त का यह मानना सही था कि वह विभाजन का दावा करने की हकदार थी। ट्रिब्यूनल इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि 1937 अधिनियम को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 31 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने ऐप के साथ असहमत होकर सहायक आयुक्त को बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 एक का अधिकार देती है। एचयूएफ के बंटवारे का दावा करने वाली महिला संपत्ति। ट्रिब्यूनल ने अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा भरोसा किए गए दो निर्णयों को अलग किया और दली चंद तेज राय बनाम सी.आई.टी. का पालन किया।[3] राजस्थान उच्च न्यायालय का एक निर्णय, जिसमें यह माना गया कि एक हिंदू महिला को एच.यू.एफ. के विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। निर्धारिती ने संदर्भ मांगा और ट्रिब्यूनल ने हमारी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है:

---

[1] एआईआर 1974 गुजरात 23.

[2] 1974 राजस्व कानून रिपोर्ट 327।

[3] 97 आई.टी.आर. 383.

“चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण का यह मानना कानूनन सही था कि एक विधवा मां और उसके बेटे के बीच एचयूएफ की संपत्ति का वैध आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है?

(4) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और ट्रिब्यूनल के आदेश और मामले के बयान के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि इस मामले के बुनियादी स्वीकृत तथ्यों की पूरी तरह से गलतफहमी हुई है। यदि विवाद का निपटारा एच.यू.एफ. के सह-साझेदारों के सदस्यों के बीच किया जाना था। और प्रश्न उठाए गए कि क्या 3 सितंबर, 1963 को राम चंदर पालीवाल की मृत्यु से संयुक्त हिंदू परिवार बाधित हो गया था और यदि यह बाधित हुआ तो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी क्या होगी, इस पर क्या विचार किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस विचार के लिए गिर गया होगा। यहां, आयकर अधिकारी और न्यायाधिकरण को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 171 के तहत मामले का निर्धारण करने के लिए बुलाया गया था। माना जाता है कि एच.यू.एफ. इसमें राम नारायण, उनकी मां, राम प्यारी, उनकी पत्नी और उनके नाबालिग बेटे और एच.यू.एफ. शामिल थे। राम चंदर पालीवाल की मृत्यु, जो 3 सितंबर, 1963 को हुई थी, के बावजूद 1963 से 31वें मैच, 1973 तक इसे मान्यता दी गई और इसका मूल्यांकन जारी रखा गया। उपरोक्त अधिकारियों के सामने मुद्दा यह नहीं था कि क्या एच.यू.एफ. करदाता हो सकता है या नहीं। संदर्भित प्रश्न से भी,

यह स्पष्ट है कि एक एच.यू.एफ. है। और। जो निर्धारित किया जाना है वह है
क्या एच.यू.एफ. का आंशिक विभाजन है? संपत्ति वैध थी या नहीं।

(5) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा एच.यू.एफ. का निपटारा किया गया है। किसी अन्य संस्था का भागीदार बन सकता है। एक बार एच.यू.एफ. 31 मार्च 1973 तक करदाता बने रहने पर एच.यू.एफ. का आंशिक विभाजन हो सकता है। संपत्ति और वह यह है कि इस मामले में क्या किया गया है। एच.यू.एफ का आंशिक विभाजन मेसर्स राम नारायण सत नारायण की साझेदारी फर्म में संपत्ति का कारोबार राम नारायण द्वारा किया गया था और चूंकि उनकी मां उनके साथ संपत्ति को समान रूप से साझा करने की हकदार थीं, इसलिए उन्हें भी बराबर हिस्सा दिया गया और विभाजन का ज्ञापन तैयार किया गया। इन परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम की धारा 171 को पढ़ने पर, हमें एचयूएफ के आंशिक विभाजन का दावा करने के लिए निर्धारिती के रास्ते में कोई बाधा नहीं दिखती है। संपत्तियां। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मां बंटवारे का दावा करने की हकदार थी या नहीं, और अगर राम नारायण एकमात्र पुरुष सह-वारिसदार था, तो भी वह बंटवारा कर सकता था। आयकर कानून और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 171 में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि यदि एच.यू.एफ. के सदस्य। माँ और बेटे हैं, ऐसे H.U.F. एच.यू.एफ. का पूर्ण या आंशिक विभाजन करने में कानूनन वर्जित है। संपत्तियां।

तर्क की इस प्रक्रिया पर, हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही नहीं था कि एच.यू.एफ. का वैध आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है। एक विधवा मां और उसके बेटे के बीच संपत्ति, और संदर्भित प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दें, अर्थात, निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध।

(6) संदर्भ को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटाया जाता है।

एन.के.एस.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा